

(ख) पीपी का अधिक से अधिक उत्पादन बढ़ाने और नुक़ के मूल्य को उचित सीमा में बनाये रखने से बन्धी उपायों पर सरकार राज्य सरकारों के परामर्श से विचार कर रही है और इनकी घोषणा आगामी विराई मौसम के शुरू होने से पूर्व कर दी जायेगी।

राजस्थान में पर्यटन

5247. श्री श्रींकार लाल बेरवा : क्या पर्यटन तथा श्रैलैनिक उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिये गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितनी रकम नियत की गई है ;

(ख) इस रकम को किस प्रकार खर्च करने का विचार है ; और

(ग) क्या उदयपुर, चित्तौड़ जोधपुर, जैसलमे, रामनगर और भाबू में पर्यटकों के लिये होटल तथा याता सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये विशेष रूप से कुछ रकम नियत की गई है ?

पर्यटन तथा श्रैलैनिङ उद्योग मंत्री (श्री. श्रीं सिन्) : (क) 1967-68 के दौरान राजस्थान में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय योजना ने 2.50 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। इसके मुकाबले 1966-67 ने राज्य सरकार को उत्पादन के रूप में 24,986 रुपये दिये गये।

(ख) 2.50 लाख रुपये की राशि को जयपुर और भरतपुर में पर्यटन योजनाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग) जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, माउण्ट भाबू, चित्तौड़गढ़, और अजमेर में पर्यटक आवास और/या सुविधाओं की व्यवस्था करने की योजनाएँ हैं। राज्य सरकार से इस बात की पुष्टि हो जाने के बाद कि वे 50 प्रतिशत व्यय वहन करेंगे उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

महाराष्ट्र को खाद्य का निर्यात तथा उसकी सप्लाई

5248. श्री देवराज भाटिल :
श्री रा० शि० भण्डारे :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने महाराष्ट्र राज्य को जनवरी, 1967 से लेकर जून, 1967 की अवधि में, उसके लिए नियत अनाज के मासिक कोटे के अनुसार अनाज की पूरी मात्रा सप्लाई नहीं की गई ;

(ख) यदि हाँ, तो नियत मासिक कोटे की मात्रा क्या थी और बस्तुतः कितने अनाज की सप्लाई की गई ; और

(ग) अनाज की कितनी कम मात्रा सप्लाई की गई और इस कटौती के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्डे) : (क) से (ग) कुछ महीनों में कुछ कम सप्लाई हुई थी जबकि अन्य महीनों में अधिक सप्लाई हुई थी। महाराष्ट्र को जनवरी से जून, 1967 तक आयातित खाद्यान्नों (गेहूँ और माहलो) के आवंटित कोटे और उन कोटों के प्रति वास्तव में की गई सप्लाई इस प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

	आवंटित कोटा	सप्लाई
जनवरी, 67	97.7	95.2
फरवरी, 67	95.0	103.8
मार्च, 67	90.2	90.0
अप्रैल, 67	80.0	67.2

मई, 67	80.0	83.9
जून, 67	70.3	61.7
जोड़	513.2	501.8

सप्ट ई में कमी लगभग 2.2 प्रतिशत थी। सप्टाई ने कमी कम धामद होने के कारण हुई थी।

पंजाब तथा हरियाणा द्वारा बिहार को धनाज का भंडा जाना

5249. श्री रामावतार साहू :
श्री योगेश झा :
श्री क० बि० मधुकर :

क्या जाह, तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के राज्य मंत्री गेहूँ, जौ, झुंड़ी तथा चना खरीदने के बारे में बातचीत करने के लिये पंजाब और हरियाणा गये थे;

(ख) क्या दोनों राज्यों की सरकारें बिहार को धनाज बेचने के लिये तैयार हैं, यदि उन्हें केन्द्रीय सरकार से इसकी अनुमति मिल जाये और उनके मार्ग में और कोई बाधाएँ न आयें; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार को इन दो राज्यों से धनाज खरीदने की अनुमति देने के लिये सहमत है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जाह, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सूक्ष्मकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). सूचना दक्षिण की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

Increase in Food Output

5250. श्री Marandi: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Agricultural Prices Commission has refuted the official claim that a 10% term growth rate of 2.5 per cent to 3 per cent a year in food output has already been reached; and

(b) if so, the grounds therefor and the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anasahib Shinde): (a) and (b) The Agricultural Prices Commission have not contested the compound rate of growth of 3.16 per cent per annum achieved in the production of cereals over the period 1949-50 to 1964-65. They have pointed out that the rate of growth comes down, if the period over which the rate is to be measured is reduced from 15 years to smaller durations ranging from 10 to 14 years, and by successively bringing forward the base year of estimation from 1949-50. They have also referred to the exceptionally poor production during the drought years of 1965-66 and 1966-67. The Commission have, therefore, expressed that "whatever may be the achievements in individual States and with individual crops, no firm assertions can really be made about the realised rates of growth at the national levels"

High Yielding Crop Programme in Punjab

5251. श्री Yajna Datt Sharma: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) the acreage and the credit requirement for the high yielding variety crop programme in Punjab during the year 1967-68;

(b) whether the entire credit requirement will be made available by the Reserve Bank of India; and